एस.एस. कांग और डी.वी. सहगल से पहले, जे.जे.

ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,- अपीलकर्ता.

बनाम

चंद्रावली और अन्य,- प्रतिवादी।

1984 के आदेश क्रमांक 272 से प्रथम अपील

5 दिसंबर 1989.

साक्ष्य अधिनियम (1872 का प्रथम)–एस.एस. 64, 65, 66–मोटर वाहन अधिनियम (IV1939 का)–एस. 95–सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V)–ओ. बारहवीं, आरएलएस। 2 और 3ए-द्वितीयक साक्ष्य-स्वीकार्यता-प्रमाण-इनकी प्रतिलिपि-बीमा पॉलिसी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई और प्रदर्शित की गई - पूर्वमूल प्रति प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकतानुसार मालिक को नोटिस नहीं दिया गया एस. 66 द्वारा - अपीलीय चरण में स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति -ऐसी प्रति का संभावित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

माना गया कि बीमाकर्ता को धारा 66 के तहत आवश्यक था साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत पहले मालिक को नोटिस दिया गया था बीमा की मूल पॉलिसी प्रस्तुत करने तथा ऐसा न करने पर इसलिए यह सीएल के तहत अपनी प्रति तैयार कर सकता था। (ए) एस का 65. कोई नहीं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या द्वारा अपेक्षित कदम हालाँकि, अधिनियम बीमाकर्ता द्वारा लिया गया था। इसलिए, यह नहीं हो सका कार्यवाही के अंतिम चरण में बस ऊपर की एक प्रति

में बीमा की पॉलिसी और इसे विवरण के माध्यम से एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करें इसके परामर्श का|

माना गया कि O. XII, RI. संहिता के 2 में प्रावधान है कि कोई भी पक्ष किसी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए दूसरे पक्ष को बुला सकता है और यदि ऐसा हो बाद वाले ऐसा करने में लापरवाही करते हैं तो निश्चित परिणाम सामने आते हैं। एक महत्वपूर्ण विचार-आरएल द्वारा निर्धारित प्रश्न. 2-ए यह है कि न्यायालय, दिए गए में परिस्थितियाँ, दस्तावेज़ को स्वीकृत माना जाए। आरएल के तहत. 3 ए यहां तक कि बिना पूर्व सूचना के भी, अदालत किसी भी पक्ष को बुला सकती हैकिसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार करें. जहां एक दस्तावेज़ को एक पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है|जिसके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वह औपचारिक है|इसे साक्ष्य में स्वीकार करने से पहले प्रमाण आवश्यक नहीं है। सभी में अन्य मामलों में किसी दस्तावेज़ को उसके प्रमाण पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है|अधिनियम के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार। जो कुछ भी दस्तावेज़, इसका उपयोग साक्ष्य के रूप में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह वास्तविक न हो या तो स्वीकार किया गया है या प्रमाण द्वारा स्थापित किया गया है जो होगा दस्तावेज़ को न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किए जाने से पहले दिया गया। इसलिए,इसके बावजूद इसे पूर्व के रूप में चिह्नित किया गया है। आर. बीमा पॉलिसी की 1 प्रति इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया गया है और इसका प्रमाण नहीं है से विमुक्त नहीं किया गया है।

यह माना गया कि मन का कोई सचेतन प्रयोग नहीं किया गया न्यायाधिकरण इस प्रश्न पर कि क्या जारी करने की आवश्यकता है|धारा 66 के तहत उस मालिक को नोटिस दिया जाना चाहिए, जो अंदर होना चाहिए बीमा की मूल पॉलिसी का अधिकार या अधिकार होना चाहिए के साथ तिरस्कृत। कोर्ट का कोई विशेष आदेश भी नहीं है स्वीकार-साक्ष्य के रूप में बीमा की पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करना। दरअसल,बीमाकर्ता के वकील के बयान का कोई मतलब नहीं है|बीमा की पॉलिसी की प्रतिलिपि के प्रमाण और औपचारिक निविदा के लिए प्रमाण के रूप में।

(1) यू पीओ किन और अन्य बनाम यू एसओ गैल (एआईआर 1939 रंगून 275)।

(2) उमर-उद-दीन बनाम गुलाम मोहम्मद और दूसरा एआईआर 1935 लाह. 628. (से असहमत)

(यह मामला माननीय श्री न्यायमूर्ति द्वारा बड़ी बेंच को भेजा गया था|1 सितम्बर 1988 को एस.एस.सोढ़ी को एक महत्वपूर्ण फैसले के लिए इस मामले में शामिल कानून का प्रश्न. डिवीजन बेंच में शामिल हैं-माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग और माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.वी. का कार्यकाल।सहगल ने 5 तारीख को इस मामले से जुड़े कानून के सवाल पर फैसला सुनाया दिसंबर, 1988 और मामला वापस लर्नड सिंगल को भेज दिया गया गुण-दोष के आधार पर निर्णय लें। अंततः मामले का निर्णय हुआ माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. सोढ़ी 26 मई, 1989 को)।

श्री ए. पी. चाउ के न्यायालय के आदेश से प्रथम अपील-धारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नारनौल, दिनांक 30 नवंबर, 1983, रुपये की सीमा तक याचिका की अनुमति दी गई। 760 एक्स 12X 10 = 91,200 आनुपातिक लागत और ब्याज की दर से याचिका की तारीख से तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष भुगतान और आगे आदेश देना कि बीमा कंपनी पुनः-संख्या 3 पुरस्कार को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दावा: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत आवेदन।

अपील में दावा : निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता एस.के. शर्मा।एम. एस. सिंगला एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या' के लिए 1 से 4.श्री प्रबोध मित्तल एवं जसवन्त जैन एडवोकेट के साथ हरि मित्तल-प्रतिवादी संख्या 6 के लिए, उद्धरण।

निर्णय दिनांक 5 दिसंबर, 1988 पारित किया गया

माननीय डिवीजन बेंच।

डी. वी. सहगल, जे.

1. इसमें शामिल कानून के प्रश्नों से निपटने के उद्देश्य से, तथ्यों को विस्तार से बताना आवश्यक नहीं है। यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि जिस वाहन मेटाडोर की पंजीकरण संख्या HRM-1808 है, जिसके कारण अतर सिंह की मृत्यु हुई, उसका बीमा ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (संक्षेप में 'बीमाकर्ता') से किया गया था। मृतक की विधवा और बच्चों (संक्षेप में 'दावेदारों') द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-ए के तहत किए गए दावे के आवेदन पर , मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') ने फैसला सुनाया। उनके पक्ष में रु. 91,200/- मुआवजे के रूप में यह मानते हुए कि दुर्घटना उक्त वाहन की तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी। 1984 का एफएओ नंबर 232 उन दावेदारों द्वारा दायर किया गया है जिनकी शिकायत है कि दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है। 1984 का एफएओ नंबर 272 बीमाकर्ता द्वारा है, जो अन्य आधारों पर ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने के अलावा, तर्क देता है कि बीमा की नीति के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए उसकी देनदारी रुपये तक सीमित है। 50,000/-. ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा आवेदन के परीक्षण के चरण में, बीमाकर्ता ने कोई सबूत पेश नहीं किया। हालाँकि, इसके वकील ने 20-9-1983 को निम्नलिखित आशय का एक बयान दिया: -

"मैं बीमा पॉलिसी Ex. RI की सच्ची प्रति प्रस्तुत करता हूं और अपना साक्ष्य बंद करता हूं।"

2. बीमा की पॉलिसी की प्रति। आरएल का तात्पर्य बीमाकर्ता के सहायक मंडल प्रबंधक द्वारा सच्ची प्रति के रूप में सत्यापित होना है। इसे ट्रिब्यूनल के समक्ष 20-3-1983 को पेश किया गया था जब उपरोक्त बयान इसके वकील द्वारा दिया गया था। बीमाकर्ता के वकील द्वारा उपरोक्त कथन और बीमा की पॉलिसी की प्रति को पूर्व के रूप में चिह्नित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। आरएल को दावेदारों द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष ले जाया गया था। हालाँकि, इसकी स्वीकार्यता पर उनके द्वारा विवाद किया गया था जब उपरोक्त अपीलें एसएस सोढ़ी, जे के

समक्ष सुनवाई के लिए आईं। उन्होंने मैसर्स में मेरे फैसले पर भरोसा रखा। मालवा बस सर्विस (पी.) लिमिटेड मोगा, जिला फरीदकोट बनाम अमृत कौर, (1987) 91 पन एलआर 618, जिसमें मैंने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा--

"वर्तमान मामले में प्रतिवादी 1 ने इस तथ्य से इनकार करते हुए झूठी दलील दी कि बस का बीमा किया गया था। इस प्रकार, एक बार यह साबित हो जाए कि यह दलील गलत है और बस वास्तव में प्रतिवादी 8 के साथ बीमाकृत थी, तो उसे उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए मुआवजे की पूरी राशि का भुगतान। प्रतिवादी 8 के विद्वान वकील ने, हालांकि, बचाव में दो दलीलें दी हैं। सबसे पहले, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि बीमा पॉलिसी को नियम 1 और ए के रूप में विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड पर लाया गया है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी 8 का दायित्व उस राशि तक सीमित था जो अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। हालाँकि, मैंने पाया कि नियम 1 केवल बीमा पॉलिसी की एक प्रति है। इसे प्रस्तुत किया गया था मामले को बंद करने के चरण में वकील के बयान द्वारा साक्ष्य। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 64 में प्रावधान है कि दस्तावेजों को धारा 65 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। धारा 65 में कहा गया है कि द्वितीयक साक्ष्य किसी दस्तावेज़ से संबंधित उसके अस्तित्व, स्थिति या सामग्री के बारे में उस स्थिति में बताया जा सकता है जहां मूल दिखाया गया है या उस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में प्रतीत होता है जिसके खिलाफ दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की गई है या किसी बाहर के व्यक्ति के न्यायालय की प्रक्रिया तक पहुंच या इसके अधीन नहीं, या इसे पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किसी व्यक्ति की, और जब, धारा 66 में उल्लिखित नोटिस के बाद , ऐसा व्यक्ति इसे पेश नहीं करता है। दूसरे, किसी दस्तावेज़ का साक्ष्य वहां भी प्रस्तुत किया जा सकता है जहां मूल नष्ट हो गया है या खो गया है, या जब इसकी सामग्री का साक्ष्य देने वाला पक्ष, अपनी गलती या उपेक्षा से उत्पन्न न होने वाले किसी भी कारण से, इसे उचित समय में प्रस्तुत नहीं कर सकता है या, जहां धारा 65 में निर्दिष्ट कोई भी शर्त मौजूद है। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी शर्त साबित नहीं हुई है, इसलिए बीमा पॉलिसी की प्रति। आरएल, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं था क्योंकि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 की

शर्तों को पूरा नहीं किया गया था। बीमा पॉलिसी की प्रति। इसलिए, आरएल को साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।"

3. दूसरी ओर, बीमाकर्ता द्वारा गोपाल दास बनाम श्री ठाकुरजी , एआईआर 1943 पीसी 83, डोगर मल बनाम सुनाम राम, एआईआर 1944 लाह 58, यू पो किन बनाम यू सो गेल, एआईआर 1936 पर भरोसा रखा गया था। रंग 277, और उमर-उद-दीन बनाम गुलाम मोहम्मद , एआईआर 1935 लाह 628। उसी के सामने, विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि मेसर्स में मेरी टिप्पणियाँ। मालवा बस सर्विस के मामले (1987-91 पुन एलआर 618) (सुप्रा) पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, मामला एक बड़ी बेंच को भेजा गया था और इस प्रकार इसे हमारे सामने रखा गया है।

4. यह मामला कानून के निम्नलिखित प्रश्नों को जन्म देता है:--

(1) क्या बीमा की पॉलिसी को उसकी प्रति प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। जब तक साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में अधिनियम') की धारा 65 के अर्थ के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का मामला नहीं बनाया गया हो ?

(2) क्या बीमा की पॉलिसी की प्रति को पूर्व के रूप में अंकित किया गया है। क्या आरएल को साक्ष्य में स्वीकार करना है और कानून के अनुसार इसके प्रमाण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है?

(3) यदि प्रश्न संख्या (1) और (2) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या अपीलीय न्यायालय विचार से बाहर कर सकता है। आर1 जब ट्रिब्यूनल के समक्ष इसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति नहीं की गई?

5. मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-सी की उप-धारा (2) ट्रिब्यूनल को दस्तावेजों की खोज और उत्पादन के लिए सिविल कोर्ट की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') में निहित इस संबंध में प्रावधान ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं। अधिनियम की धारा 1 , अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करती है कि यह किसी भी

न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए हलफनामों पर नहीं, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि न्यायालय में सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और मध्यस्थों को छोड़कर सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत हैं। इसलिए, अधिनियम के प्रावधान ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही पर लागू होते हैं। बीमाकर्ता ने 17-12-1982 को ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर अपने लिखित बयान में अपनी प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 5 में निम्नलिखित दलील दी: -

"यदि दावा याचिका सफल हुई तो उत्तर देने वाला केवल 50,000/- रुपये की सीमा तक उत्तरदायी है क्योंकि किसी एक दावे या घटना से उत्पन्न दावों की श्रृंखला के संबंध में बीमा 50,000/- रुपये तक सीमित था। ।"

. 6. दावेदार ने अपनी प्रतिकृति में इस दावे का खंडन किया और इस प्रकार कहा -

"लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्तियों का पैरा नंबर 5 गलत है, और इसलिए अस्वीकार कर दिया गया है। याचिका प्रतिवादी बीमा कंपनी के खिलाफ भी दावा की गई राशि के लिए विचारणीय है।"

7. आदेश VIII, संहिता के नियम 8-ए में कहा गया है कि जहां एक प्रतिवादी अपने बचाव को अपने कब्जे या शक्ति में किसी दस्तावेज़ पर आधारित करता है, तो वह इसे अदालत में तब पेश करेगा जब लिखित बयान उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसी समय उसे अदालत में पेश करना होगा। समय, दस्तावेज या उसकी एक प्रति, लिखित बयान के साथ दाखिल करने के लिए सौंपें, एक दस्तावेज जो इस नियम के तहत प्रतिवादी द्वारा अदालत में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से पेश नहीं किया गया है, अदालत की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा, सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य प्राप्त किए जाएं। हालाँकि, आश्चर्यजनक रूप से, बीमाकर्ता ने अपने लिखित विवरण के साथ बीमा पॉलिसी की एक प्रति संलग्न नहीं की।

8. बीमा की मूल पॉलिसी, निश्चित रूप से, बीमाकर्ता के कब्जे में नहीं हो सकती है। यह बीमाकृत वाहन के मालिक (संक्षेप में 'मालिक') के कब्जे और शक्ति में माना जाता है। इसलिए, बीमाकर्ता को मालिक को शपथ पर इसकी खोज करने का निर्देश देने के आदेश के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करना चाहिए था। ट्रिब्यूनल, किसी भी समय, उसके समक्ष दावे के लंबित रहने के दौरान, मालिक द्वारा बीमा की मूल पॉलिसी को प्रस्तुत करने का कानूनी रूप से आदेश दे सकता है। ऐसे कदम संहिता के आदेश XI, नियम 12 और 14 द्वारा प्रमाणित हैं। बीमाकर्ता बीमा की पॉलिसी या उसकी प्रति स्वीकार करने के लिए मालिक और दावेदारों को बुला सकता है। इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने में उनकी विफलता संहिता के आदेश XII द्वारा निर्धारित परिणामों को जन्म दे सकती है।

9. अधिनियम की धारा 64 में कहा गया है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए। बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बीमा पॉलिसी Ex, R1 की प्रति मूल के अस्तित्व, स्थिति और सामग्री के द्वितीयक साक्ष्य की प्रकृति में है और अन्य बातों के साथ-साथ धारा 65 में निर्धारित निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी दी जा सकती है : --

(ए) जब मूल दिखाया जाता है या कब्जे या शक्ति में प्रतीत होता है--

उस व्यक्ति की जिसके विरुद्ध दस्तावेज़ को साबित करने की मांग की गई है या।

किसी ऐसे व्यक्ति की पहुंच से बाहर/या जो न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन नहीं है, या कानूनी रूप से इसे पेश करने के लिए बाध्य किसी व्यक्ति की, और जब, धारा 66 में उल्लिखित नोटिस के बाद , ऐसा व्यक्ति इसे पेश नहीं करता है;

(बी) जब मूल के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री को उस व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वीकार किया गया हो जिसके खिलाफ यह साबित हुआ है या उसके हित में प्रतिनिधि द्वारा;

(सी) जब मूल नष्ट हो गया हो या खो गया हो, या जब इसकी सामग्री का साक्ष्य देने वाला पक्ष किसी अन्य कारण से, जो उसकी अपनी चूक या उपेक्षा से उत्पन्न न हो, उचित समय में इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता है;

(डी) जब मूल ऐसी प्रकृति का हो कि आसानी से हिलाया न जा सके।"

10. अधिनियम की धारा 66 के तहत बीमाकर्ता को बीमा की मूल पॉलिसी प्रस्तुत करने के लिए मालिक को पहले नोटिस देना आवश्यक था और ऐसा करने में विफल रहने पर वह धारा 65 के खंड (ए) के तहत इसकी प्रति प्रस्तुत कर सकता था । . हालाँकि, संहिता या अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई भी कदम बीमाकर्ता द्वारा नहीं उठाया गया था। इसलिए, कार्यवाही के अंतिम चरण में यह केवल बीमा पॉलिसी की एक प्रति नहीं दे सकता है और इसे अपने वकील के बयान के माध्यम से एक प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित नहीं कर सकता है। इसलिए, प्रश्न संख्या (1) का उत्तर नकारात्मक है।

11. आदेश XII, संहिता के नियम 2 में प्रावधान है कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए बुला सकता है और यदि बाद वाला ऐसा करने में उपेक्षा करता है तो निश्चित परिणाम होंगे। उपरोक्त नियम 2-ए द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि न्यायालय, दी गई परिस्थितियों में, दस्तावेज़ को स्वीकार्य मानेगा। उपरोक्त नियम 3-ए के तहत, बिना किसी पूर्व सूचना के भी, न्यायालय किसी भी पक्ष को किसी भी दस्तावेज़ को स्वीकार करने के लिए बुला सकता है। जहां किसी दस्तावेज़ को किसी पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसके विरुद्ध इसे साक्ष्य के रूप में पेश करने की मांग की जाती है, तो साक्ष्य में स्वीकार किए जाने से पहले इसका औपचारिक प्रमाण आवश्यक नहीं है। अन्य सभी मामलों में किसी दस्तावेज़ को अध्याय के प्रावधानों के अनुसार उसके प्रमाण पर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अधिनियम के वी. दस्तावेज़ जो भी हो, उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी वास्तविकता को या तो स्वीकार नहीं किया गया हो या सबूत द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो जो दस्तावेज़ को न्यायालय द्वारा प्रदर्शित किए जाने से पहले दिया जाएगा। इसलिए, इसके पूर्व

के रूप में चिह्नित होने के बावजूद। बीमा पॉलिसी की आर1 प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इसके प्रमाण को समाप्त नहीं किया गया है। इसलिए, प्रश्न संख्या (2) का उत्तर नकारात्मक है।

12. इसके पहले के प्रश्नों के उत्तर के आलोक में तीसरे और अंतिम प्रश्न के दो पहलू हैं। सबसे पहले, वह पूर्व. आरएल को अधिनियम की धारा 65 के तहत मामला बनाए बिना बीमा की मूल पॉलिसी के द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था । दूसरा, इसे Ex के रूप में चिह्नित किया गया था। आरएल इसकी सामग्री को दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार किए बिना और इसे कानून के अनुसार साबित किए बिना। इसलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय पूर्व को बाहर कर सकता है। यू पो किन के मामले (एआईआर 1936 रंग 277) (सुप्रा) में ट्रिब्यूनल के समक्ष इसकी स्वीकार्यता और सबूत के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं होने पर विचार से आरएल, रंगून उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार आयोजित किया -

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 66 के तहत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए उस पक्ष को पहले ही नोटिस दिया जाना चाहिए जिसके पास या शक्ति में दस्तावेज़ है, इसकी सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य देने से पहले, लेकिन कुछ मामलों में स्वीकार्य द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए ऐसा नोटिस आवश्यक नहीं है उदाहरण के लिए, जहां न्यायालय अपने विवेक से इसे समाप्त करना उचित समझता है; हालांकि आपत्ति साक्ष्य प्राप्त करने के समय उठाई जानी चाहिए और द्वितीयक की स्वीकार्यता के संबंध में अपीलीय न्यायालय में कोई आपत्ति लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वह साक्ष्य जिसे ट्रायल कोर्ट में बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था।"

13. यू पो किन्स केस (एआईआर 1936 रंग277) (सुप्रा) का अनुपात वहां लागू किया जा सकता है जहां कुछ शर्तें लागू होती हैं; अर्थात् जहां न्यायालय अपने विवेक से मूल दस्तावेज़ के कब्जे या शक्ति वाले पक्ष को धारा 66 के तहत नोटिस देना उचित समझता है और जहां दस्तावेज की प्रति बिना किसी आपत्ति के ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती है।

14. जैसा कि वर्तमान मामले के तथ्यों के संक्षिप्त विवरण से देखा जा सकता है, ट्रिब्यूनल द्वारा इस सवाल पर दिमाग का कोई सचेत उपयोग नहीं किया गया था कि क्या मालिक पर धारा 66 के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता है। बीमा की मूल पॉलिसी पर कब्ज़ा या अधिकार होना समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बीमा की पॉलिसी की प्रति को साक्ष्य में स्वीकार करने का न्यायालय का कोई विशेष आदेश भी नहीं है। दरअसल, पूरी बात डीटी के बयान से शुरू और खत्म हुई। बीमाकर्ता के वकील की 20-9-1983 जिसके द्वारा उसने बीमा पूर्व की पॉलिसी की सच्ची प्रति प्रस्तुत की। आरएफ और उसका मामला बंद कर दिया. बीमा पॉलिसी की प्रति का प्रस्तुतीकरण अपने आप में इसके उत्पादन और साक्ष्य में प्रवेश के बराबर नहीं हो सकता है। जैसा कि बलदेव सहाय बनाम राम चंदर , एआईआर 1931 लाह 546 में एक डिवीजन बेंच ने कहा था , दस्तावेजों से संबंधित दो चरण हैं। एक वह चरण है जब वे सभी दस्तावेज़ जिन पर पार्टी भरोसा करती है, न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं। अगला चरण तब होता है जब दस्तावेज़ों को साबित किया जाता है और औपचारिक रूप से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह मानना मुश्किल है कि दस्तावेज़ के उत्पादन और प्रवेश के दोनों चरण एक साथ हुए। वास्तव में, बीमाकर्ता के वकील का बयान किसी भी तरह से बीमा पूर्व की पॉलिसी की प्रति के प्रमाण और औपचारिक निविदा के बराबर नहीं है। साक्ष्य में आर.एल.

15. उमर-उद-दीन के मामले में (एआईआर 1935 लाह 628) (सुप्रा), यह एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आयोजित किया गया था कि जहां किसी कार्य की सामग्री का द्वितीयक साक्ष्य दूसरे पक्ष की आपत्ति के बिना दिया जाता है, वहां आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है दूसरी अपील में. हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण इसके विपरीत है और इसे लागू किया जाना चाहिए। सीतल दास बनाम संत राम , एआईआर 1954 एससी 606, एक ऐसा मामला था जहां एक पंजीकृत वसीयत की प्रति पर भरोसा किया गया था। 7-10-1911. इस दस्तावेज़ को किसी भी गवाह द्वारा साबित नहीं किया गया था और न ही इस पर कोई प्रदर्शन चिह्न था। अंतिम न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 65 के तहत द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई आधार नहीं रखा गया था और न ही प्रस्तुत प्रति को धारा 63 के अर्थ में

द्वितीयक साक्ष्य माना जा सकता है । रोमन कैथोलिक मिशन बनाम मद्रास राज्य , एआईआर 1966 एससी 1457, एक ऐसा मामला था जहां अधीनस्थ न्यायाधीश, मधुराई के न्यायालय के एक पुराने मामले के रिकॉर्ड से कुछ पट्टों की प्रमाणित प्रतियां पूर्व के रूप में पेश की गईं थीं। बी-4, 5, 6 और ए-68, 69 और 77, इन दस्तावेजों की मूल प्रतियां किसी भी समय ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गईं। अपीलकर्ताओं के पक्ष में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जिला न्यायाधीश ने दस्तावेजों की इन प्रदर्शित प्रमाणित प्रतियों पर विचार किया। हालाँकि, अपील में उच्च न्यायालय ने इसे विचार से बाहर कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की (एआईआर के पृष्ठ 1461 पर):-

"किसी भी स्तर पर मूल प्रस्तुत नहीं किए गए थे और न ही द्वितीयक साक्ष्य देने के अधिकार की स्थापना के लिए कोई नींव रखी गई थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया और ऐसा करना स्पष्ट रूप से सही था। हम इन दस्तावेजों को विचार से बाहर रखते हैं, अन्य दस्तावेज़ यह नहीं दिखाते कि इनाम में कुडीवरम भी शामिल था।"

16. इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यू पो किन का मामला (एआईआर 1936 रंग 277) (सुप्रा) और उमरेउद-डिंग मामला (एआईआर 1935 लाह 628) (सुप्रा) अच्छा कानून नहीं बनाते हैं।

17. निम्नलिखित टिप्पणियों को गोपाल दास के मामले में जगह मिलती है (एआईआर 1943 पीसी 83) (सुप्रा):--

"जहां आपत्ति यह नहीं है कि दस्तावेज़ अपने आप में अस्वीकार्य है, बल्कि यह कि सामने रखे गए सबूत का तरीका अनियमित या अपर्याप्त है, यह आवश्यक है कि दस्तावेज़ को एक प्रदर्शन के रूप में चिह्नित करने से पहले परीक्षण में आपत्ति ली जानी चाहिए और रिकॉर्ड में स्वीकार किया गया। कोई भी पक्ष तब तक झूठ नहीं बोल सकता जब तक मामला अपील की अदालत के सामने नहीं आ जाता और फिर सबूत के तरीके के तहत पहली बार शिकायत नहीं करता।"

18. उपरोक्त टिप्पणियों को लागू करने से पहले, एक निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए कि दस्तावेज़ अपने आप में स्वीकार्य नहीं है। पूर्व के संबंध में ऐसा नहीं है। रोमन कैथोलिक मिशन के मामले (एआईआर 1966 एससी 1457) (सुप्रा) में निर्धारित कानून के मद्देनजर आरएल। डोगर मल के मामले में एक डिवीजन बेंच (एआईआर 1944 लाह 58) (सुप्रा) ने इस प्रकार कहा-

"किसी दस्तावेज़ के प्रमाण का तरीका प्रक्रिया का प्रश्न है और इसे माफ किया जा सकता है। जब किसी दस्तावेज़ के प्रमाण के तरीके के बारे में आपत्ति जैसे कि खाता पुस्तकों में प्रविष्टियों को औपचारिक प्रमाण के बिना नहीं देखा जा सकता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। उस समय लिया गया जब दस्तावेज़ को निचली अदालत में साबित करने की मांग की गई थी और दस्तावेज़ को पार्टियों और अदालत द्वारा स्वतंत्र रूप से संदर्भित किया गया था, इसे दूसरी अपील में पहली बार उठाने में बहुत देर हो चुकी है।"

19. यदि उपरोक्त टिप्पणियों का अर्थ यह लगाया जाए कि जहां किसी पार्टी की खाता पुस्तकों में प्रविष्टियां विवाद में हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट में आपत्ति के अभाव में बिना औपचारिक सबूत के साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित की जाती हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। अपील में, संबंध में यह कहा गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

20. सैत ताराजी खिमचंद बनाम येलामर्ती सत्यम , एआईआर 1971 एससी 1865 में, अन्य बातों के साथ-साथ यह इस प्रकार देखा गया था (एआईआर के पृष्ठ 1868 पर) -

"वादी क्रमशः एक्सएस ए-12 और ए-13, डे-बुक और लेजर पर भरोसा करना चाहते थे। वादी ने इन पुस्तकों को साबित नहीं किया। फैसले में इन पुस्तकों का कोई संदर्भ नहीं है। केवल एक का अंकन प्रदर्शनी दस्तावेज़ों के प्रमाण के बिना नहीं है,"

21. इस प्रकार, इस प्रस्ताव के लिए डोगर मल के मामले (एआईआर 1944 लाह 58) (सुप्रा) पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि चूंकि पूर्व। आरएल

प्रदर्शित कर दिया गया है, इसका औपचारिक प्रमाण खारिज कर दिया गया है और इसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति अपील में नहीं ली जा सकती है।

22. इसलिए, प्रश्न संख्या (3) का उत्तर सकारात्मक है।

23. बीमाकर्ता के लिए विद्वान वकील के प्रति पूरी निष्पक्षता में यह उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जुगल किशोर , 1988 ऐस सीजे 270: (एआईआर 1988 एससी 719) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया था। विशेष रूप से निम्नलिखित टिप्पणियों पर (आकाशवाणी के पृष्ठ 721 पर): --

"प्रस्तुति से निपटने से पहले हम यह बता सकते हैं कि जिस पॉलिसी के तहत बस का बीमा किया गया था, वह न तो ट्रिब्यूनल के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। पॉलिसी की एक फोटोस्टेट कॉपी, हालांकि, इस न्यायालय में दायर की गई है और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को इसे साक्ष्य में स्वीकार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी।"

24. यह समझना कठिन है कि ये टिप्पणियाँ बीमाकर्ता के लिए किस प्रकार सहायक हो सकती हैं। उत्तरदाताओं के वकील को बीमा पॉलिसी की फोटोस्टेट कॉपी को साक्ष्य में स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ निश्चित रूप से ऐसा मामला नहीं है।

25. ऊपर दिए गए कानून के सवालों के मद्देनजर, यह अपील अब गुण-दोष के आधार पर फैसले के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस जाएगी।

एसएस कांग, जे.

26. मैं सहमत हूं.|

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
बहादुरगढ़,हरियाणा